

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 715
24 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मेगा फूड पार्क और शीतागार श्रृंखला परियोजनाएं

715. श्री शंकर लालवानी:

श्री आलोक शर्मा :

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्री मन्ना लाल रावत:

श्री कंवर सिंह तंवर:

श्री भोजराज नाग:

श्री दामोदर अग्रवाल:

श्री दिलेश्वर कामैत :

श्री चिन्तामणि महाराज:

श्री भरतसिंह शंकरजी डाभी:

डॉ. हेमांग जोशी:

श्री राजकुमार चाहर:

सुश्री कंगना रनौत:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित/ स्वीकृत मेगा फूड पार्क और शीतागार श्रृंखला परियोजनाओं की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी निधि व्यय की गई है;
- (ख) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं/उप-योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अमरोहा और झांसी जिले तथा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कोई परियोजना स्वीकृत की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या यह योजना किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने और कृषि उपज की बर्बादी को कम करने में प्रभावी और सहायक रही है;
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में, विशेषकर उक्त जिलों में इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और
- (च) महाराष्ट्र राज्य और पालघर जिले में पीएमकेएसवाई की उपलब्धियों/कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में इस योजना के माध्यम से कितने रोजगार सृजित हुए हैं?

उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)**

- (क): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित मेगा फूड पार्क (एमएफपी) और शीत श्रृंखला (सीसी) परियोजनाओं की संख्या तथा व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।
- (ख): पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।
- (ग): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एक केन्द्रीय क्षेत्र की मांग आधारित योजना है और पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्यवार धनराशि आवंटित/स्वीकृत/जारी नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा और झांसी तथा हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले सहित पूरे भारत से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मौजूदा योजना

दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता की जांच की जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर अनुमोदन दिया जाता है। अमरोहा और झांसी जिलों में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-3** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में अब तक किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ): पीएमकेएसवाई योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है जिसमें भंडारण, परिवहन आदि शामिल हैं, जिससे किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने में मदद मिलती है। खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से, कृषि उपज की मांग जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल है, बढ़ जाती है जिससे किसानों को बेहतर कीमतें मिलती हैं और खेत पर लाभप्रदता बढ़ जाती है। दिनांक 30.06.2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत, 1601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1133 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिससे देश में 3,41,5102 किसान, उत्तर प्रदेश राज्य में 2,14,243 किसान और अमरोहा जिले में 1,121 किसान लाभान्वित हुए हैं। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) द्वारा वर्ष 2020 में "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत कार्यान्वित इकाइयों के प्रभाव" पर किए गए और मंत्रालय को प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, यह रेखांकित किया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना के हस्तक्षेप के कारण, जबकि सभी क्षेत्रों में अपव्यय में कुछ कमी देखी गई, लेकिन फल और सब्जियां, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में अपव्यय में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।

(च): महाराष्ट्र राज्य में पीएमकेएसवाई योजना का ब्यौरा **अनुबंध-4** में दिया गया है। पालघर जिले में स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा **अनुबंध-5** में दिया गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में 58,691 रोजगार सृजित किए गए हैं।

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर हेतु पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मेगा फूड पार्क और शीत शृंखला परियोजनाओं के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 715 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	मेगा फूड पार्क		कोल्ड चेन	
		स्वीकृत परियोजनाएँ	जारी की गई सहायता अनुदान राशि (करोड़ में)	स्वीकृत परियोजनाएँ	जारी की गई सहायता अनुदान राशि (करोड़ में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0	1	2.81
2	आंध्र प्रदेश	3	132.1	34	228.31
3	अरुणाचल प्रदेश	1	12.02	2	6.46
4	असम	1	48.84	2	17.37
5	बिहार	2	47.05	5	34.86
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	1	39.57	3	11.52
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0
11	गुजरात	2	84.36	27	192.65
12	हरियाणा	2	62.55	23	134.65
13	हिमाचल प्रदेश	1	45	17	133.91
14	जम्मू और कश्मीर	1	29.03	6	40.33
15	झारखंड	0	0	0	0
16	कर्नाटक	2	86.29	16	98.06
17	केरल	2	87.8	8	21.19
18	लद्दाख	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	2	89.37	12	70.57
21	महाराष्ट्र	3	103.94	76	442.28
22	मणिपुर	1	9.49	1	9.96
23	मेघालय	1	5.38	0	0
24	मिजोरम	1	44.62	2	12.77
25	नागालैंड	1	38.78	3	8.39
26	ओडिशा	2	82.75	8	43.19
27	पुडुचेरी	0	0	0	0
28	पंजाब	3	121.38	24	138.4
29	राजस्थान	2	58.39	14	78.58
30	सिक्किम	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	1	13.27	23	101.95
32	तेलंगाना	2	73.48	16	93.9
33	त्रिपुरा	1	45	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	0	27	183.85
35	उत्तराखंड	2	97.79	30	255.57
36	पश्चिम बंगाल	1	45	15	79.65
	कुल	41	1503.25	395	2441.18

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर हेतु पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मेगा फूड पार्क और शीत शृंखला परियोजनाओं के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 715 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अन्बंध

[illegible]

मध्य प्रदेश	4	2	22	8	1	1	12	8	2	2	8	7	1	0	0	0	2	2	52	30
महाराष्ट्र	13	5	78	49	11	9	76	57	3	2	32	27	7	1	21	21	4	4	245	175
मणिपुर	0	0	4	2	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	8	5
मेघालय	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3	1	1	10	6
मिजोरम	0	0	1	1	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
नागालैंड	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	2
उड़ीसा	1	0	9	2	0	0	8	4	2	1	5	4	0	0	3	1	0	0	28	12
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
पंजाब	3	1	16	11	4	4	24	21	3	2	10	7	1	0	14	14	1	1	76	61
राजस्थान	2	0	25	14	6	5	14	13	2	1	2	1	1	0	3	2	0	0	55	36
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
तमिलनाडु	12	2	32	23	9	8	23	13	1	0	23	19	4	1	41	41	0	0	145	107
तेलंगाना	4	0	23	6	1	1	16	10	2	1	8	6	0	0	12	12	1	1	67	37
त्रिपुरा	0	0	5	5	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	0	0	9	9
उत्तर प्रदेश	2	2	37	27	5	4	27	18	0	0	10	9	4	1	11	11	1	1	97	73
उत्तराखंड	0	0	18	13	4	4	30	27	2	2	4	4	0	0	1	0	0	0	59	50
पश्चिम बंगाल	0	0	17	12	1	1	15	12	1	1	12	8	0	0	8	8	0	0	54	42
कुल	68	22	525	314	61	53	395	291	41	24	205	169	44	10	236	225	26	25	1601	1133

* अनु = अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या

*प्रचा.= प्रचालनरत परियोजनाएं

**सीसी= एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना

**एफटीएल = खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना

**एपीसी = कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना के निर्माण की योजना

**सीईएफपीपीसी= खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना

**ओजी = ऑपरेशन ग्रीन्स

**आर एंड डी = मानव संसाधन और संस्थान - अनुसंधान और विकास

**कौशल = मानव संसाधन और संस्थान - कौशल विकास

**सीबीएफएल = बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना

**एमएफपी = मेगा फूड पार्क

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर हेतु पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मेगा फूड पार्क और शीत श्रृंखला परियोजनाओं के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 715 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजनाएं	राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	ज़िला	अनुमोदन का दिनांक	परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	स्थिति
एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला)	उत्तर प्रदेश	न्यूफार्म फूड्स	एफ एंड वी	अमरोहा	20-04-2017	25.62	9.19	9.19	पूर्ण
खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना (सीईएफपीपीसी)	उत्तर प्रदेश	मेसर्स आशीर्वाद व्यंजन	दूध प्रसंस्करण	अमरोहा	14.09.2018	15.78	5.00	4.89	पूर्ण
अनुसंधान एवं विकास	उत्तर प्रदेश	मूल्यवर्धित वुड एप्पल के प्रसंस्करण एवं तैयारी हेतु प्रौद्योगिकी का विकास (बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी)	सरकार	झांसी	2008-09	0.39	0.39	0.20	पूर्ण

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर हेतु पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मेगा फूड पार्क और शीत श्रृंखला परियोजनाओं के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 715 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

महाराष्ट्र राज्य में पीएमकेएसवाई की विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा										
क्र. सं.	योजना*	अनुमोदित परियोजनाएँ	पूर्ण/प्रचालनरत	परियोजना लागत (करोड़ में)	स्वीकृत सहायता अनुदान (करोड़ में)	जारी सहायता अनुदान (करोड़ में)	प्रसंस्करण (एमटी/वर्ष)	परिरक्षण (एमटी/वर्ष)	रोज़गार	लाभांविit किसान
1	एपीसी	13	5	414	119	65	3	2	14566	58700
2	बीएफएल	11	9	119	27	24	1	1	13092	60445
3	सीसी	76	57	2246	536	442	52	7	45600	725952
4	सीईएफपीपीसी	78	49	1169	291	201	25	0	28360	36127
5	एफटीएल	32	27	206	74	50	0	0	1184	0
6	एमएफपी	3	2	356	149	104	1	1	4243	5750
7	ओजी	7	1	242	97	33	3	0	17847	149800
8	अनुसंधान एवं विकास	21	21	10	10	9	0	0	0	0
9	कौशल	4	4	2	1	1	0	0	0	0
	कुल	245	175	4764.52	1305.04	927.94	84.34	10.50	124892	1036774

*सीसी= एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना

*एफटीएल = खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना

*एपीसी = कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना के निर्माण की योजना

* सीईएफपीपीसी = खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार योजना

*ओजी= ऑपरेशन ग्रीन्स

*आर एंड डी = मानव संसाधन और संस्थान - अनुसंधान और विकास

*कौशल = मानव संसाधन और संस्थान - कौशल विकास

*सीबीएफएल = बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन योजना

*एमएफपी = मेगा फूड पार्क

दिनांक 24.07.2025 को उत्तर हेतु पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मेगा फूड पार्क और शीत श्रृंखला परियोजनाओं के संबंध में अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 715 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	योजनाएं	राज्य	परियोजना का नाम	क्षेत्र	ज़िला	अनुमोदन का दिनांक	परियोजना लागत	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)	स्थिति
1	एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना (शीत श्रृंखला)	महाराष्ट्र	हेरिटेज फूड्स लिमिटेड	डेरी	पालघर	13-11-2018	46.06	9.82	9.82	पूर्ण